नंदिग्राम टाईम्स

RNI NO. MAHHIN/2016/69743 EDITOR : SHAIKH JAHUR AHEMAD

Friday 9th January 2026 | ● वर्ष - 9 | ● अंक 254 | ● पृष्ठ 04 | ● मूल्य - 2 रूपए | ● www.nandigramtimes.com

राहुल गांधी और उदित राज की बढ़ी मुसीबत, कोर्ट के सामने होना होगा हाजिर, मायावती से जुड़ा मामला भी जानिए

बदायूं: बदायूं स्थित अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम पूनम सिंगल ने कांग्रेस सासंद राहुल गांधी और उदित राज के खिलाफ नोटिस जारी किया है। राहुल गाँधी व उदित राज दोनों नेताओं को 29 जनवरी को कोर्ट में स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता को उपस्थित होने का आदेश दिया है।

कांग्रेस के नेता व पूर्व सांसद उदित राज द्वारा बसपा सुप्रीमो के खिलाफ अपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में अधिवक्ता जय सिंह सागर द्वारा दायर की फौजदारी निगरानी याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये आदेश दिया है।

अधिवक्ता जय सिंह सागर ने अनुसार 16 फरवरी 2025 को कांग्रेस के नेता व पूर्व सांसद उदित राज ने बसपा सुप्रीमो मायावती पर अपत्तिजनक बयानबाजी और उनकी हत्या करने तक की बात कही थी। उक्त संबंध में अगले दिवस 17 फरवरी को MP-MLA कोर्ट में मुकदमा दायर करने का प्रार्थना पत्र दिया गया था। जिसे MP-MLA कोर्ट ने इस घटना को दिल्ली की बताते हुए उसे खारिज कर दिया था। इसके बाद अधिवक्ता जय सिंह सागर ने 25 अगस्त 2025 को जिला जज की अदालत में फौजदारी निगरानी दायर की थी। उक्त मामले में अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट को भेजा गया था। तभी से इस मामले में सुनवाई चल रही थी।

इस मामले में अपर जिला जज व पॉक्सो एक्ट प्रथम पूनम सिंघल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पुत्र स्व.राजीव गांधी निवासी 10 जिला दिल्ली व उदित राज पुत्र स्व.कल्लन 192 नार्थ एवेन्यू निकट आरएमएल अस्पताल को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में दोनों नेताओं को अपना पक्ष रखने के लिए 29 जनवरी की तारीख निर्धारित की गई और वें स्वयं या अधिवक्ता के जरिए अपना पक्ष रख सकते है ऐसा आदेश किया गया है।

TOP NEWS | स्लीपर बसों में लापरवाही पर सरकार सख्त, गडकरी बोले–

स्लीपर बसों में लापरवाही पर सरकार सख्त, गडकरी बोले– दोषियों पर होगी सीबीआई जांच

नई दिल्ली। देश में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं और स्लीपर बसों के निर्माण में हो रही गंभीर लापरवाहियों को लेकर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने साफ कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने संकेत दिए हैं कि स्लीपर बसों के निर्माण, फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने और सुरक्षा मानकों की अनदेखी से जुड़े मामलों की जांच सीबीआई से कराई जा सकती है।

गडकरी ने कहा कि प्राइवेट बस बॉडी बिल्डरों द्वारा बड़े पैमाने पर सुरक्षा नियमों की अनदेखी की जा रही है। कई मामलों में बसें मानकों पर खरी नहीं उतरतीं, इसके बावजूद उन्हें फिटनेस सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। उन्होंने बीते वर्ष राजस्थान समेत अन्य राज्यों में स्लीपर बसों में आग लगने की घटनाओं का जिक्र करते हुए बताया कि इन हादसों में करीब 145 लोगों की दर्दनाक मौत हुई।

मंत्री ने दो टूक कहा कि अब किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार से मंत्रालय ने विस्तृत रिपोर्ट मांगी है कि इन दुर्घटनाओं के लिए कौन-कौन जिम्मेदार था और किन स्तरों पर चूक हुई। भविष्य में भी ऐसे किसी मामले में सख्त कदम उठाए जाएंगे। गडकरी ने यह भी घोषणा की कि अब देश में प्राइवेट बस वेंडर स्लीपर बसें नहीं बना सकेंगे। आगे से केवल चेसिस बनाने वाली कंपनियां ही स्लीपर बसों का निर्माण करेंगी और नए नियमों के तहत अतिरिक्त सेफ्टी फीचर अनिवार्य होंगे। सड़क सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए सरकार वी2वी यानी व्हीकल-टू-व्हीकल तकनीक पर भी काम कर रही है।

इस सिस्टम के जरिए वाहन आपस में वायरलेस तरीके से रियल टाइम जानकारी साझा करेंगे, जिससे टक्कर की आशंका कम होगी। इसे बसों और ट्रकों समेत चार पहियों से बड़े सभी वाहनों में लगाया जाएगा। सरकार ने 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में 50 प्रतिशत कमी लाने का लक्ष्य भी तय किया है। इसके तहत 100 जिलों में "जीरो फेटेलिटी डिस्ट्रिक्ट" योजना पर काम किया जा रहा है। वहीं ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर तकनीक आधारित चालान प्रणाली लागू कर मानवीय हस्तक्षेप और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की तैयारी है।

इसके अलावा सड़क दुर्घटनाओं में घायलों के लिए कैशलेस इलाज योजना को देशभर में लागू करने की घोषणा की गई है। घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले 'राहवीर' को 25 हजार रुपये का इनाम मिलेगा और सात दिन के इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। सरकार के इन कदमों से सड़क सुरक्षा में बड़ा सुधार होने की उम्मीद जताई जा रही है।

बिहार के सरकारी स्कूलों में 'अंडा घोटाला' का खुलासा, शिक्षकों की घपलेबाज़ी से हड़कंप

सीतामढ़ी (बिहार)। बिहार के सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील योजना के तहत बच्चों को वितरित होने वाले अंडों से जुड़े एक बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है, जिससे शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। सीतामढ़ी जिले के सरकारी विद्यालयों में अंडे और अन्य मिड-डे मील सामग्री के वितरण में अनियमितताओं को लेकर एक शिक्षक के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विभागीय जांच तेज़ कर दी गई। इस खुलासे में यह सामने आया है कि कुछ स्कूलों ने छात्रों की हाजिरी को 10-15 प्रतिशत ज़्यादा दिखाकर अधिक फंड लेने का स्कैम किया है, जिससे सरकारी राशि का गबन हुआ।

जांच में पाया गया कि कुछ शिक्षक दोपहर के बाद अपने अन्य कामों के लिए स्कूल छोड़ देते हैं और इस दौरान अंडों का दुरुपयोग होता है। एक ऐसे ही शिक्षक-पवन कुमार को निलंबित कर दिया गया है। डीईओ राघवेंद्र मणि त्रिपाठी ने मामले की गंभीरता के चलते त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच रिपोर्ट तैयार करने को कहा है।

यह मामला शिक्षा प्रणाली में विद्यमान भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता को उजागर करता है। विभाग अब अन्य संबंधित शिक्षकों और अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने का इरादा रखता है ताकि भविष्य में इस तरह की अनियमितताओं को रोका जा सके।

वेनेजुएला में अमेरिकी ऑपरेशन: जेडी वैंस की अनुपस्थिति ने उठे सवाल, चाणक्यनीति की हो रही चर्चा

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है। 'ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व' नाम के इस सैन्य अभियान में अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने कराकस में छापा मारकर मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को पकड़ा और न्यूयॉर्क ले जाया गया, जहां वे नार्को-टेररिज्म और ड्रग तस्करी के आरोपों का सामना कर रहे हैं।

ट्रंप ने इसे "परफेक्टली एक्जीक्यूटेड" ऑपरेशन बताते हुए वेनेजुएला के तेल संसाधनों पर अमेरिकी नियंत्रण की बात की, लेकिन इस विजय के सार्वजनिक जश्न में उपराष्ट्रपति जेडी वैंस की अनुपस्थिति ने राजनीतिक गलियारों में कानाफूसी शुरू कर दी है।

मार-ए-लागो में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस और वार रूम की तस्वीरों में विदेश मंत्री मार्को रुबियो, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ, सीआईए डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ और अन्य प्रमुख अधिकारी ट्रंप के साथ नजर आए, लेकिन वैंस कहीं नहीं थे।

सूत्रों के अनुसार, वैंस को जानबूझकर मार-ए-लागो से दूर रखा गया ताकि ऑपरेशन की गोपनीयता बनी रहे। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने इसे सुरक्षा कारण बताया, लेकिन विश्लेषक इसे गहरा राजनीतिक संकेत मान रहे हैं।

वैंस, जो इराक युद्ध के अनुभव से विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ रहे हैं और ट्रंप के "अमेरिका फर्स्ट" सिद्धांत के प्रमुख समर्थक माने जाते हैं, इस अभियान में सार्वजनिक रूप से चुप रहे।

उन्होंने बाद में एक बयान में तेल संपत्तियों को "चोरी की संपत्ति" बताते हुए ऑपरेशन का समर्थन किया, लेकिन उनका लहजा सतर्क और संयमित था। विशेषज्ञों का मानना है कि वैंस ने खुद को इस जोखिम भरे कदम से दूरी बनाई रखी, क्योंकि यह ट्रंप के पहले कार्यकाल के "नो न्यू वॉर्स" वादे से उलट लगता है।

इसी तरह, राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गैबार्ड भी इस ऑपरेशन की योजना से बाहर रखी गईं और सार्वजनिक मंचों पर अनुपस्थित रहीं। गैबार्ड, जो पहले वेनेजुएला पर अमेरिकी दबाव की आलोचना करती थीं, ने बाद में सोशल मीडिया पर सेना की तारीफ की, लेकिन उनका लहजा औपचारिक और दूर का लगा।

चाणक्यनीति की याद
भारतीय विश्लेषकों और सोशल मीडिया पर इस अनुपस्थिति को प्राचीन रणनीतिकार चाणक्य की नीति से जोड़ा जा रहा है। चाणक्य कहते थे कि सत्ता के खेल में बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा विकल्प खुले रखता है और विफलता की स्थिति में खुद को बचाता है।

वैंस की यह "रणनीतिक चुप्पी" और दूरी को इसी नजरिए से देखा जा रहा है –आज की जीत कल का बोझ न बने। वैंस का भारत से व्यक्तिगत जुड़ाव (पत्नी उषा वैंस के माध्यम से) इस तुलना को और मजबूत करता है।

ट्रंप ने कहा कि अमेरिका वेनेजुएला को "चला रहा है" और तेल की बिक्री से 30-50 मिलियन बैरल अमेरिका को मिलेंगे, लेकिन रुबियो ने इसे स्पष्ट करते हुए कहा कि कोई स्थायी कब्जा नहीं है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्राजील, कोलंबिया और मेक्सिको ने इसकी निंदा की, जबकि कुछ रिपब्लिकन इसे "अमेरिका इज बैक" का संकेत बता रहे हैं।

यह अभियान ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की सबसे बड़ी विदेश नीति कार्रवाई है, लेकिन वैंस की अनुपस्थिति से सवाल उठ रहे हैं: क्या यह आंतरिक मतभेद है या भविष्य की राजनीति की तैयारी? आने वाले दिन बताएंगे।

गुजरात में UK वीजा के लिए फर्जी शादी–तलाक स्कैम का भंडाफोड़, चार आरोपी हुए नामजद

NEWS AGENCY |

भरूच (गुजरात)। गुजरात के भरूच जिले में पुलिस ने ब्रिटेन (UK) वीजा पाने के लिए फर्जी शादी और तलाक के दस्तावेज बनाने वाले अंतरराष्ट्रीय आव्रजन घोटाले का पर्दाफाश किया है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस के अनुसार मामला उस समय खुला जब 'पति' के रूप में दिखाए गए शख्स ने पैसे के विवाद को लेकर शिकायत दर्ज कराई। जांच के दौरान पता चला कि 3.5 लाख रुपये की 'डील' के तहत एक स्थानीय महिला को UK वीजा दिलाने के लिए जाली निकाहनामा और नकली तलाक के कागजात तैयार किए गए थे।

पैलेज पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर आनंद चौधरी ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद जब मामले की तह में जाया गया, तो यह स्पष्ट हुआ कि भाड़े के शख्स रिजवान मेडा, तसलीमाबानू करभारी, उसके भाई फैजल और एक वकील साजिद कोठिया ने मिलकर यह योजना बनाई थी। नकली निकाहनामा के आधार पर वीजा प्रक्रिया पूरी की गई और महिला को UK भेज दिया गया। बाद में तलाक का नकली कोर्ट आदेश भी दायर किया गया ताकि वीजा प्रक्रिया में 'अलगाव' दिखाया जा सके।

पुलिस ने चारों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। साथ ही घटना के बारे में ब्रिटिश उच्चायोग और मिस्टर को भी सूचित किया जा रहा है, जिससे आरोपियों के संभावित प्रत्यर्पण को भी तेज़ किया जा सके।

दिल्ली में सर्दी का प्रकोप बढ़ा, शीतलहर और कोहरे के बीच येलो अलर्ट जारी

नई दिल्ली। राजधानी में तापमान में गिरावट के साथ ठंड का प्रकोप तेज़ हो गया है और मौसम विभाग (IMD) ने शीतलहर तथा कोहरे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिससे सुबह-सुबह दृश्यता कम हुई है। शुक्रवार को कई इलाकों में हल्का से भारी कोहरा छाया रहा, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया और अगले कुछ दिनों में भी ठंड की स्थिति बनी रहने की संभावना है।

IMD के अनुसार न्यूनतम तापमान गिरकर सर्दी का अहसास और बढ़ा रहा है और कोहरा विशेषकर सुबह के समय अधिक घना रहेगा, जिससे हवाई व रेल यातायात प्रभावित हो सकता है। येलो अलर्ट के मद्देनज़र लोगों को ठंड से बचने और ड्राइविंग के समय सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

पीएम मोदी ने भारतीय एआई स्टार्टअप्स के साथ की चर्चा, इनोवेशन को लेकर कह दी बड़ी बात

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अपने आधिकारिक आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर सुबह भारतीय एआई स्टार्टअप के साथ बैठक की। यह बैठक इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 से पहले हुई है, जो कि अगले महीने भारत में होने वाला है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में वह 12 एआई स्टार्टअप शामिल हुए हैं। इन्होंने एआई फॉर ऑल: ग्लोबल इम्पैक्ट चैलेंज के लिए क्वालिफाइड किया है और इसमें उन्होंने अपने विचार और कार्य के बारे में बताया।

पीएम कार्यालय की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया कि यह स्टार्टअप हेल्थकेयर, बहुभाषी लार्ज लैग्वेज मॉडल, मटेरियल रिसर्च, डेटा एनालिटिक्स, इंजीनियरिंग सिमुलेशन और अन्य क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं।

बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समाज में परिवर्तन लाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के महत्व पर प्रकाश डाला।

एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी
उन्होंने कहा कि भारत अगले महीने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा, जिसके माध्यम से देश टेक्नोलॉजी क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथ ही कहा कि भारत एआई का उपयोग करते हुए परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहा है।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि स्टार्टअप और एआई उद्यमी भारत के भविष्य के सह-निर्माता हैं और कहा कि देश में इनोवेशन और बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन दोनों की अपार क्षमता है। उन्होंने आगे कहा कि भारत को दुनिया के सामने एक ऐसा अनूठा एआई मॉडल प्रस्तुत करना चाहिए जो "मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड" की भावना को दर्शाता हो। हम पर दुनिया का भरोसा बड़ी ताकत, प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पर दुनिया का भरोसा ही देश की सबसे बड़ी ताकत है। इस कारण भारतीय एआई मॉडल नैतिक, निष्पक्ष, पारदर्शी और डेटा गोपनीयता सिद्धांतों पर आधारित होने चाहिए। साथ ही कहा कि भारत किफायती एआई, समावेशी एआई और किफायती इनोवेशन को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा दे सकता है।

उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि भारतीय एआई मॉडल विशिष्ट होने चाहिए और स्थानीय एवं स्वदेशी सामग्री तथा क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने वाले हो। इस बैठक में अवतार, भारतजेन, फ्रैक्टल, गैन, जेनलोप, ज्ञानी, इंटेलीहेल्थ, सर्वम, शोध एआई, सॉकेट एआई, टेक महिंद्रा और जेंटिक सहित भारतीय एआई स्टार्टअप्स के सीईओ, प्रमुख और प्रतिनिधि शामिल हुए। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भी बैठक में उपस्थित थे।

न्यायमूर्ति वर्मा के महाभियोग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, डिप्टी चेयरमैन की शक्तियों पर उठे सवाल

नई दिल्ली। इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही में सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिससे राजनीतिक और संवैधानिक बहस तेज़ हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वर्मा की याचिका पर सुनवाई पूरी कर दी और दोनों पक्षों को लिखित दलीलें जमा करने को कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने डिप्टी चेयरमैन की शक्तियों पर गहन सवाल उठाए हैं।

न्यायमूर्ति वर्मा ने लोकसभा अध्यक्ष द्वारा गठित जांच समिति की वैधता को चुनौती दी है। उनका तर्क है कि राज्यसभा में डिप्टी चेयरमैन द्वारा महाभियोग प्रस्ताव को खारिज किए जाने के बाद लोकसभा स्पीकर द्वारा समिति का गठन असंवैधानिक है। वर्मा के वकीलों ने कहा कि डिप्टी चेयरमैन के पास इस प्रकार की संवैधानिक शक्तियां नहीं थीं और महाभियोग प्रक्रिया को तब तक स्थगित किया जाना चाहिए था जब तक नया राज्यसभा चेयरमैन नियुक्त न हो जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया इस दलील से असहमति जताई है कि जब राज्यसभा में प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ, तब लोकसभा स्पीकर समिति क्यों गठित कर सकते हैं। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता को पहले ही समय विस्तार दिया जा चुका है, इसलिए आगे की मांग को खारिज कर दिया गया। अब फैसला सुरक्षित रखने के बाद कोर्ट के अंतिम आदेश का इंतजार है।

यह मामला भारतीय संविधान में महाभियोग प्रक्रिया और संसद के दोनों सदनों की भूमिकाओं की संवैधानिक सीमाओं पर महत्वपूर्ण बहस को जन्म दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट की गम्भीर टिप्पणियों के बाद यह प्रश्न उभर रहा है कि क्या डिप्टी चेयरमैन महाभियोग प्रस्ताव पर निर्णय लेने की अधिकारिक स्थिति में हैं या नहीं, जो आगे की सुनवाई में स्पष्ट होगा।

महाराष्ट्र के महानगरपालिका चुनाव: शहरों का भविष्य तय करने की घड़ी

संपादकीय... |

महाराष्ट्र आज एक बार फिर अपने शहरी भविष्य के निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। 8 जनवरी 2026 को राज्य में चल रहे महानगरपालिका चुनाव केवल राजनीतिक दलों के लिए सत्ता की लड़ाई नहीं हैं, बल्कि आम नागरिक के लिए यह सवाल तय करने का अवसर हैं कि उसके शहर किस दिशा में बढ़ेंगे। मुंबई, नागपुर, छत्रपति संभाजीनगर, अकोला, लातूर, नांदेड सहित महाराष्ट्र की अन्य महानगरपालिकाओं में यह चुनाव शहरी शासन, विकास और लोकतांत्रिक जवाबदेही की सच्ची परीक्षा बन चुके हैं।

महानगर किसी भी राज्य की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक धड़कन होते हैं। महाराष्ट्र के महानगरों ने देश को उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अनेक अवसर दिए हैं, लेकिन इसके साथ ही यहां समस्याओं का बोझ भी लगातार बढ़ता गया है। अनियोजित शहरीकरण, बुनियादी सुविधाओं पर बढ़ता दबाव और प्रशासनिक शिथिलता ने महानगरपालिका व्यवस्था की सीमाओं को उजागर कर दिया है। ऐसे में यह चुनाव केवल प्रतिनिधि चुनने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि व्यवस्था सुधारने का जनादेश भी हैं।

हर चुनाव में 'विकास' सबसे बड़ा नारा बनकर उभरता है। इस बार भी स्मार्ट सिटी, विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सेवाएं और निवेश के बड़े-बड़े वादे किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन वादों का लाभ आम नागरिक तक पहुंचा है? महानगरों की सड़कों पर गड्ढे, पानी की अनियमित आपूर्ति, कचरे के ढेर, जाम से जूझता ट्रैफिक और सिकुड़ती सार्वजनिक जगहें कुछ और ही कहानी कहती हैं। विकास की चमकदार तस्वीर और ज़मीनी हकीकत के बीच की यह खाई ही इस चुनाव की सबसे बड़ी चुनौती है।

राजनीतिक दृष्टि से देखें तो इस बार का चुनावी मुकाबला अत्यंत रोचक और जटिल है। प्रमुख दलों के बीच सीधा संघर्ष है, तो वहीं गठबंधन और समीकरण मतदाताओं को उलझा रहे हैं। टिकट वितरण को लेकर असंतोष, बागी उम्मीदवारों की मौजूदगी और आंतरिक गुटबाजी ने चुनावी माहौल को और तीखा बना दिया है। लेकिन इस राजनीतिक शोरगुल के बीच यह आशंका भी है कि कहीं असली मुद्दे—नागरिक सुविधाएं, पारदर्शिता और जवाबदेही—हाशिये पर न चले जाएं।

महानगरपालिका की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी सीमित स्वायत्तता रही है। चुनी हुई महापालिकाएं अक्सर वित्तीय संसाधनों और निर्णयों के लिए राज्य सरकार पर निर्भर रहती हैं। इससे स्थानीय समस्याओं का समाधान समय पर नहीं हो पाता। यदि शहरी प्रशासन को वास्तव में प्रभावी बनाना है, तो कर संग्रह, बजट उपयोग और प्रशासनिक निर्णयों में पारदर्शिता और स्वतंत्रता अनिवार्य होगी। यह विषय चुनावी बहस के केंद्र में होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से इस पर गंभीर चर्चा कम ही होती है।

भ्रष्टाचार और जवाबदेही का सवाल भी महानगरपालिका राजनीति से अलग नहीं है। निर्माण कार्यों, ठेकों और निविदाओं को लेकर उठते आरोप नागरिकों के विश्वास को कमजोर करते हैं। ई-टेंडरिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म समाधान का रास्ता दिखाते हैं, लेकिन जब तक निगरानी और दंड की ठोस व्यवस्था नहीं होगी, तब तक व्यवस्था पर भरोसा बहाल करना कठिन रहेगा। मतदाता को यह समझना होगा कि पारदर्शिता कोई वैकल्पिक सुविधा नहीं, बल्कि सुशासन की बुनियाद है।

इस चुनाव में शहरी मध्यम वर्ग, युवा और महिलाएं निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। महानगरों में शिक्षा और जागरूकता का स्तर ऊंचा है, फिर भी मतदान प्रतिशत अक्सर निराशाजनक रहता है। यदि यही वर्ग मतदान से दूर रहा, तो निर्णय सीमित समूहों के हाथ में चला जाएगा। युवाओं के लिए रोजगार, सार्वजनिक परिवहन, पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षित शहर जैसे मुद्दे केवल भाषणों तक सीमित न रहें—यह जिम्मेदारी मतदाता को ही निभानी होगी।

महिलाओं की भागीदारी भी केवल आरक्षण तक सीमित न रहे, बल्कि नीति निर्धारण और शहरी नियोजन में उनकी प्रभावी भूमिका सुनिश्चित हो—यह अपेक्षा भी इस चुनाव से जुड़ी है। सुरक्षित सड़कें, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और समावेशी सार्वजनिक स्थान तभी संभव हैं, जब निर्णय प्रक्रिया में विविध दृष्टिकोण शामिल हों।

अंततः, मुंबई, नागपुर, छत्रपति संभाजीनगर, अकोला, लातूर, नांदेड और महाराष्ट्र की अन्य महानगरपालिकाओं में हो रहे ये चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का माध्यम नहीं हैं। यह शहरों की आत्मा, उनकी कार्यसंस्कृति और नागरिकों के भविष्य को तय करने का अवसर हैं। यदि मतदाता सजग होकर सवाल पूछे, घोषणाओं से आगे बढ़कर काम का हिसाब मांगे और स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता दे, तो यही महानगरपालिका चुनाव महाराष्ट्र के शहरी लोकतंत्र को नई दिशा दे सकते हैं।

आज आवश्यकता है ऐसे प्रतिनिधियों की, जो चुनाव जीतने के बाद भी नागरिकों के बीच रहें, जवाबदेह हों और शहर को केवल चुनावी नक्शे पर नहीं, बल्कि जीवन के हर स्तर पर बेहतर बनाने की इच्छाशक्ति रखें। महानगरों का भविष्य अब नारों से नहीं, निर्णयों से तय होगा—और इसका पहला कदम मतदान केंद्र से होकर गुजरता है।

WORLD NEWS | सऊदी-UAE में भीषण तनाव, फिर व्यापार पर असर क्यों नहीं?

न बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपैया... सऊदी-UAE में भीषण तनाव, फिर व्यापार पर असर क्यों नहीं?

अबू धाबी: यमन में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में चरम पर तनाव है। दोनों देश एक दूसरे पर आक्रामक हैं और सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप लगा रहे है। इसके बावजूद उनके 30 बिलियन डॉलर का व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत हो रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि सऊदी और यूएई एक दूसरे का बहिष्कार नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों का बहुत कुछ दांव पर लगा है। 2017 में सऊदी अरब और यूएई ने कतर का बहिष्कार किया था। सऊदी अरब और UAE व्यापार, निवेश और लॉजिस्टिक को लेकर एक दूसरे पर काफी निर्भर है। ऐसे में विश्लेषकों का कहना है कि पूरी तरह से आर्थिक दरार पड़ने की संभावना नहीं है।

क्या यूएई का बहिष्कार करेगा सऊदी

जून 2017 में, सऊदी अरब, UAE, बहरीन और मिस्र ने कतर के साथ संबंध तोड़ लिए थे। इन देशों ने कतर पर क्षेत्रीय अशांति फैलाने, आतंकवाद का समर्थन करने और ईरान के साथ दोस्ती का आरोप लगाया था।

हालांकि, कतर ने तब इन आरोपों को खारिज कर दिया था। तनाव इतना बढ़ गया था कि इन देशों ने कतर की नाकेबंदी कर दी थी। अपने व्यापार और यात्रा सबंध भी रातोंरात तोड़ दिए थे। लेकिन, कतर पर इस नाकेबंदी का ज्यादा असर नहीं पड़ा था।

सऊदी-यूएई व्यापार डेटा देखें

सऊदी अरब के डेटा के अनुसार, 2013 के अंत तक सऊदी अरब का यूएई के साथ द्विपक्षीय वार्षिक व्यापार 30 अरब डॉलर था। इसमें 2020 के बाद लगभग 42% की वृद्धि हुई है। 2023 में यूएई, सऊदी अरब का पांचवां सबसे बड़ा निर्यातक देश था। हालांकि, इस दौरान यूएई, सऊदी अरब का तीसरा सबसे बड़ा आयातक भी रहा।

सऊदी और यूएई एक दूसरे पर कितने निर्भर

सऊदी अरब और यूएई व्यापार के लिए एक दूसरे पर काफी निर्भर हैं। सऊदी अरब, यूएई से रिफाइंड पेट्रोलियम और सोने से लेकर आभूषण और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सामानों का आयात करता है। इस व्यापार का अधिकांश हिस्सा दुबई के जेबेल अली बंदरगाह से होकर गुजरता है। इसे सऊदी अरब के बाजार में प्रवेश करने वाले सामानों के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में देखा जाता है। यही कारण है कि सऊदी अरब अब सीधे शिपमेंट को हासिल करने के लिए अपने बंदरगाहों का विस्तार कर रहा है।

सऊदी-यूएई का एक दूसरे के देश में कितना निवेश

UAE के डेटा के अनुसार, सऊदी अरब में अमीरात का निवेश 9.2 बिलियन डॉलर से अधिक है। वहीं, UAE में सऊदी का सीधा निवेश 4.3 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। यूएई में में 4,000 से ज्यादा सऊदी ट्रेडमार्क और दर्जनों कमर्शियल एजेंसियां काम करती हैं, साथ ही लॉजिस्टिक्स, रिटेल और हॉस्पिटैलिटी में जॉइंट वेंचर भी हैं।

TOP NEWS | बांग्लादेश में दीपू दास लिंचिंग का मुख्य आरोपी गिरफ्तार

बांग्लादेश में दीपू दास लिंचिंग का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने यासीन अराफात के बारे में क्या कहा

● Reporter Name

ढाका: बांग्लादेश पुलिस ने गारमेंट फैक्ट्री वर्कर दीपू दास की लिंचिंग के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दीपू दास पर ईशनिंदा के आरोप लगाया गया था और भीड़ ने पीट-पीटकर उनकी हत्या कर दी थी। इसके बाद दीपू दास के शव को सरेआम जला दिया गया था। बांग्लादेश की पुलिस ने बताया है कि दीपू दास की लिंचिंग के मुख्य आरोपी का नाम यासीन अराफात है। वह पेशे से शिक्षक रहा है। उसने ही दीपू दास पर हमले की योजना बनाई और उसे अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई।

18 दिसंबर को हुई थी दीपू दास की हत्या

18 दिसंबर को मैमनसिंह जिले में 27 साल के दीपू दास को उसके फैक्ट्री सुपरवाइजरों ने ईशनिंदा के आरोप में इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। इसके बाद से उन्हें काम की जगह से बाहर निकाल दिया गया और कट्टरपंथियों की गुस्साई भीड़ के हवाले कर दिया गया। भीड़ ने दीपू दास को पीट-पीटकर मार डाला, उनके शव को लटका दिया और आग लगा दी। बताया जाता है कि उनके साथ काम करने वाले कर्मचारियों ने भी उन्हें मारने में भीड़ का साथ दिया था।

हत्या के बाद फरार हो गया था यासीन अराफात

पुलिस ने बताया है कि दीपू दास की हत्या के बाद गुरुवार को गिरफ्तार किया गया अराफात मौके से फरार हो गया था और छिप गया था। अधिकारियों के अनुसार, उसने हमले की साजिश रची, दूसरों को इकट्ठा होने और दास को निशाना बनाने के लिए उकसाया।

दीपू दास लिंचिंग का मुख्य आरोपी गिरफ्तार

बताया जाता है कि स्थानीय समुदाय में उसके नेतृत्व ने उसे जल्दी से एक बड़ा समूह जुटाने में मदद की, जिससे स्थिति एक जानलेवा हमले में बदल गई।

अराफात ने ही दीपू दास को घसीटा और पेड़ से लटकाया

पुलिस ने आगे कहा कि अराफात ने न केवल भीड़ को उकसाया, बल्कि उसे खुद एक चौराहे तक घसीटा, जहां उसे एक पेड़ से लटका दिया गया और आग लगा दी गई। बताया जाता है कि अराफात स्थानीय निवासी है और एक मस्जिद में पढ़ाता था। शिक्षक के रूप में उसकी स्थिति अब जांच के दायरे में है। बांग्लादेशी अधिकारी यह जांच कर रहे हैं कि क्या उसका प्रभाव हमले की तात्कालिक घटनाओं से परे भी था। अराफात की गिरफ्तारी के साथ, इस मामले में कुल गिरफ्तारियों की संख्या 21 हो गई है।

WORLD NEWS | डोनाल्ड ट्रंप के आगे क्यों झुक गए कोलंबिया के राष्ट्रपति

डोनाल्ड ट्रंप के आगे क्यों झुक गए कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो, मिला दिया फोन, जाएंगे वॉइट हाउस

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोलंबिया के अपने समकक्ष गुस्तावो पेट्रो को वॉइट हाउस में आमंत्रित किया है। ट्रंप ने कहा कि उनकी कोलंबिया के राष्ट्रपति के साथ सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई है। पेट्रो पर तीखे जवाबी हमलों के बाद डोनाल्ड ट्रंप के रुख में यह अचानक बड़ा बदलाव है। ट्रंप ने बुधवार रात ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर कहा, कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो से बात करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात रही। पेट्रो ने मादक पदार्थ की स्थिति और हमारे बीच हुए अन्य मतभेदों को समझाने के लिए फोन किया था। ट्रंप ने कहा कि वह निकट भविष्य में उनसे मुलाकात को लेकर आशान्वित हैं और बताया कि वॉइट हाउस में उनसे मुलाकात होगी।

वेनेजुएला पर हमले का तीखा विरोध

ट्रंप का यह बयान वेनेजुएला में अमेरिकी अभियान के बाद आया है, जिसमें अमेरिकी सेना ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया था। ट्रंप का पेट्रो से मुलाकात के लिए तैयार होना आश्चर्यजनक है। इसकी वजह है कि कोलंबिया नेता ने जिस मजबूती से वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले की आलोचना की है, शायद ही दुनिया के किसी नेता ने की है।

कोलंबियाई राष्ट्रपति पेट्रो ने पड़ोसी देश वेनेजुएला पर हमले को लैटिन अमेरिकी संप्रभुता का घिनौना उल्लंघन और गुलाम बनाने वालों का हमला कहा है। पेट्रो की आलोचना के अपने मायने हैं। खासतौर पर जब कोलंबिया इस इलाके में अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी रहा है। पिछले 30 वर्षों में अमेरिका ने दुनिया में कोकीन के सबसे बड़े उत्पादक कोलंबिया के साथ मिलकर ड्रग तस्करों को पकड़ने, विद्रोही समूहों से निपटने और ग्रामीण इलाकों में आर्थिक विकास के लिए मिलकर काम किया है।

प के साथ पेट्रो ने छेड़ी जुबानी जंग

हालांकि, जब दुनिया के बाकी देश वेनेजुएला पर हमले को लेकर सावधानी से अपने शब्द चुन रहे थे, उसी समय पेट्रो ने ट्रंप के साथ जुबानी जंग को बढ़ा दिया। ट्रंप की सैन्य धमकियों के विरोध में पेट्रो ने विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया, जिसके चलते बुधवार को देश भर में हजारों कोलंबियाई लोग सार्वजनिक जगहों पर जमा हुए।

ट्रंप को गुस्तावो ने किया फोन

कोलंबियाई बेसब्री के साथ गुस्तावो के संबोधन का इंतजार कर रहे थे कि आज वह ट्रंप के ऊपर नया हमला करेंगे। लेकिन कोलंबिया राष्ट्रपति ने सभी को हैरान करते हुए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। राजधानी बोगोटा में भीड़ को संबोधित करते हुए पेट्रो ने कहा, मैंने आज के लिए भाषण तैयार किया था लेकिन मुझे अब दूसरा भाषण देना होगा।

पेट्रो ने बताया कि कुछ मिनट पहले ही उन्होंने ट्रंप के साथ दोस्ताना बात की थी और समझाया था कि ड्रग तस्करी से उनका एकमात्र संबंध इसके खिलाफ लड़ने की उनकी प्रतिबद्धता है। बता दें कि ट्रंप ने पेट्रो को ड्रग माफिया कहा था। पेट्रो ने बताया कि 'मैंने हमारी सरकारों के बीच सीधी बातचीत फिर से शुरू करने के लिए कहा है।' ट्रंप और पेट्रो के बयानों से पता चलता है कि अपने मतभेदों के बावजूद दोनों में बातचीत की मेज पर आने की इच्छा है।

महाराष्ट्र विशेष

कोकण > पश्चिम महाराष्ट्र > मराठवाड़ा > विदर्भ

नंदिग्राम टाईम्स

Friday 9th January 2026 वर्ष - 9 , अंक 254 , पृष्ठ 03

पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2025-26 के लिए राज्य स्तरीय चयन परीक्षण में भाग लेने की अपील

नांदेड, 8 जनवरी (जिमाका,नांदेड़) : केंद्र सरकार के निर्देशानुसार पहली बार आयोजित किए जा रहे खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2025-26 का आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य में किया जाएगा। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के लिए राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर चयन परीक्षण आयोजित किए जा रहे हैं। यह प्रतियोगिता पुरुष एवं महिला खिलाड़ियों के खुले आयु वर्ग में आयोजित होगी।

इस प्रतियोगिता में कुल सात खेल विधाओं को शामिल किया गया है, जिनमें फुटबॉल, हॉकी, तैराकी, भारोत्तोलन, तीरंदाजी, कुश्ती एवं एथलेटिक्स का समावेश है। राज्य स्तरीय चयन परीक्षण में चयनित खिलाड़ी एवं टीमें आगे राष्ट्रीय चयन परीक्षण के लिए पात्र होंगी। राष्ट्रीय स्तर पर चयन के पश्चात अंतिम राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा।

केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार संबंधित खेलों की एकल राज्य संघटनाओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर राज्य स्तरीय चयन परीक्षण का कार्यक्रम तय किया गया है। 13 जनवरी 2026 को विभिन्न खेलों के लिए चयन परीक्षण आयोजित किए जाएंगे।

तीरंदाजी, कुश्ती एवं भारोत्तोलन के चयन परीक्षण अमरावती में होंगे। हॉकी के लिए चयन परीक्षण नेवासा, जिला अहिल्यानगर, एथलेटिक्स के लिए पालघर जिला, तैराकी के लिए महाळुंगे-बालेवाड़ी, पुणे, जबकि फुटबॉल के चयन परीक्षण नागपुर में आयोजित किए जाएंगे। यह चयन परीक्षण केवल अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe) वर्ग के खिलाड़ियों के लिए है। खिलाड़ियों के पास जाति प्रमाणपत्र, महाराष्ट्र अधिवास प्रमाणपत्र तथा मूल आधार कार्ड होना अनिवार्य है। सभी खिलाड़ियों को चयन परीक्षण में स्वखर्च से भाग लेना होगा। आवास एवं भोजन की व्यवस्था केवल खिलाड़ियों के लिए की जाएगी। खिलाड़ियों को आवश्यक खेल सामग्री एवं सुरक्षा उपकरण स्वयं लाना होगा।

चयन परीक्षण में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों को 12 जनवरी 2026 से पूर्व संबंधित संपर्क अधिकारियों के पास नामांकन कराना अनिवार्य है। व्यक्तिगत खेलों में तीरंदाजी से प्रत्येक श्रेणी के पहले तीन खिलाड़ी, जबकि कुश्ती, एथलेटिक्स, तैराकी एवं भारोत्तोलन में पहले दो खिलाड़ी राष्ट्रीय चयन परीक्षण के लिए पात्र होंगे। हॉकी एवं फुटबॉल जैसे सामूहिक खेलों में उत्कृष्ट टीम का चयन किया जाएगा। चयन परीक्षण में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को कोई प्रमाणपत्र प्रदान नहीं किया जाएगा।

नांदेड जिले के अधिक से अधिक अनुसूचित जनजाति वर्ग के खिलाड़ियों से इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाने की अपील जिला क्रीड़ा अधिकारी जयकुमार टेंभरे ने की है। अधिक जानकारी के लिए जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय, जिला क्रीड़ा संकुल, इनडोर हॉल, नांदेड में कार्यालयीन समय के दौरान संपर्क किया जा सकता है।

NWMC ELECTION | नांदेड में शिंदे सेना में अंतर्गत संघर्ष, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खुद समन्वय के लिए मैदान में

नांदेड में शिंदेसेना में मतभेद तीव्र, डैमेज कंट्रोल के लिए उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खुद कर रहे हैं हस्तक्षेप

नांदेड : महाराष्ट्र निकाय नांदेड-वाघाळा महानगरपालिका चुनावों से पहले शिंदेसेना (एकनाथ शिंदे गुट) के अंदर गुटबाजी का संघर्ष गंभीर रूप ले रहा है, जिससे पार्टी नेतृत्व को नुकसान नियंत्रण (डैमेज कंट्रोल) के लिए खुद उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को नांदेड दौरे पर आना पड़ रहा है |

यह विवाद मुख्यतः नगर निगम चुनाव में टिकट वितरण और स्थानीय नेताओं के बीच मतभेद को लेकर शुरू हुआ है। नांदेड उत्तर क्षेत्र के प्रभाग क्रमांक 3 में टिकट को लेकर उठे वाद ने अब दो विधायक और अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच टकराव को जन्म दे दिया है। पार्टी के ओएसडी गजानन पाटील की पत्नी मीनल पाटील को अधिकृत प्रत्याशी न चुनने के फैसले के बाद नाराजगी बढ़ गई। इसके बजाय श्याम कोकाटे की पत्नी अरुणा भीमराव कोकाटे को टिकट दिया गया, जिससे स्थानीय स्तर पर असंतोष फैल गया | पाटील ने अधिकृत टिकट न मिलने पर अपक्ष उम्मीदवार के रूप में चुनाव में उतरणे का निर्णय लिया और प्रचार अभियान भी शुरू कर दिया, जबकि कुछ वरिष्ठ पार्टी नेताओं ने भी खुलकर उनके पक्ष में समर्थन जताया। इस बीच, पार्टी संपर्क प्रमुख सिद्धराम म्हैत्रे की बैठक में भी इस विवाद का समाधान नहीं हो पाया, जिससे संगठन में तनाव और बढ़ गया

नांदेड दक्षिण में जहां शिंदेसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बीच गठबंधन के तहत टिकट वितरण हुआ है, वहीं उत्तर में दोनों दल आमने-सामने हैं। इस असमंजस की स्थिति ने स्थानीय नेताओं को अलग-अलग मोड़ पर खड़ा कर दिया है, जिससे शिवसेना कार्यकर्ताओं के मन में अनिश्चय की स्थिति उत्पन्न हो गई है

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के आंतरिक विवाद से सत्ताधारी गठबंधन को चुनावी माहौल में नुकसान हो सकता है, खासकर तब जब महाराष्ट्र भर में निकाय चुनाव की तैयारियाँ जोरों पर हैं। ऐसे में पार्टी उच्च नेतृत्व का हस्तक्षेप आवश्यक माना जा रहा है, ताकि संगठन को एकजुट रखा जा सके और आगामी चुनाव में समन्वय बिगड़े नहीं

शिंदे के नांदेड आगमन से पहले ही अन्य सत्ताधारी दलों के साथ गठबंधन-रणनीतिक मुद्दों पर भी गतिशीलता देखने को मिल रही है, जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में चुनावी हलचल और बढ़ती जा रही है।

"मुंबईकर" पर राज ठाकरे के बयान का पलटवार: देवेंद्र फडणवीस ने दिया तीखा जवाब

संवाददाता |

नागपुर : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे के 'मुंबईकर' बयान पर करारा जवाब दिया है। राज ठाकरे ने हाल ही में कहा था कि मुंबई में जन्मे व्यक्ति ही शहर के वास्तविक मुद्दों को समझ सकता है और बाहरी लोग इसे नहीं समझते। इस टिप्पणी के बाद फडणवीस ने स्पष्ट किया कि मुंबई में जन्म न लेना कोई दोष नहीं है और उन्होंने खुद को "सर्टिफाइड नागपूरकर" बताया।

फडणवीस ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि राज ठाकरे ने उन्हें "मुंबई के बाहर का" कहना उचित नहीं है और इसका वह सकारात्मक अर्थ निकाल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मुंबई का विकास सिर्फ मुंबई में जन्मे लोगों के कारण नहीं हुआ, बल्कि राज्य और केंद्र सरकारों की संयुक्त कोशिशों से हुआ है। उन्होंने पूर्व के 55 उड़ान पुल और वांद्रे-वरळी सी लिंक जैसे बुनियादी ढांचे का हवाला देते हुए बताया कि इन परियोजनाओं ने मुंबई के विकास को नई दिशा दी है।

फडणवीस ने यह दावा भी किया कि नितीन गडकरी, उन्होंने स्वयं और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की नीतियों के चलते मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य शहरों का समग्र विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि यह केवल किसी एक शहर या किसी के जन्म स्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यापक स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन का नतीजा है।

मुख्यमंत्री ने यह भी ज़ोर देते हुए कहा कि विकास की वजहें स्पष्ट हैं और जनता खुद इस बदलाव को महसूस कर रही है। उन्होंने राज ठाकरे की आलोचनाओं का सामना करते हुए कहा कि राजनीति में मुद्दों पर चर्चा होना चाहिए न कि जन्म स्थान को लेकर बयानबाज़ी। राज ठाकरे के बयान और फडणवीस की प्रतिक्रिया के बीच यह राजनीतिक बहस बीएमसी चुनाव 2026 के संदर्भ में चल रही है, जहाँ दोनों दल राजनीतिक मुद्दों को लेकर आमने-सामने हैं। चुनावों के मद्देनज़र यह बयानबाज़ी महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल को और तेज कर रही है।

शिवसेना प्रत्याशी हाजी सलीम कुरैशी पर जानलेवा हमला, CCTV फुटेज से संदिग्ध हमलावरों की तलाश जारी

मुंबई: डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना प्रत्याशी हाजी सलीम कुरैशी पर बुधवार को बांद्रा (ईस्ट) के संत ज्ञानेश्वर नगर में एक रैली के दौरान किसी ने कथित तौर पर चाकू से हमला कर दिया। मौके पर मौजूद हाजी के समर्थकों ने उन्हें बाइक से बांद्रा (वेस्ट) स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। खेरवाड़ी पुलिस ने अग्यात लोगों के खिलाफ हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया। आरोपी को पकड़ने के लिए जोनल डीसीपी और मुंबई क्राइम ब्रांच ने तीन टीमें बनाई गई हैं।

कुरैशी को पेट में आई चोटें

जोन 8 के डीसीपी मनीष कलवानिया ने बताया कि आरोपी के गिरफ्तार होने के बाद ही हमले का मकसद पता चलेगा। उन्होंने कहा कि शाम 5 बजे संत ज्ञानेश्वर नगर में रैली के दौरान कुरैशी के पेट पर कुछ चोटें आई। वह खतरे से बाहर हैं। पुलिस टीमें फील्ड में काम कर रही हैं। खेरवाड़ी के एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि हमला अनजान लोगों ने किया था जिससे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। हालांकि, पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और हालात को कंट्रोल में किया। शिवसेना बीएमसी चुनावों में बीजेपी के साथ गठबंधन में लड़ रही है।

कौन हैं हाजी सलीम कुरैशी

AIMIM मुंबई के पूर्व जनरल सेक्रेटरी हाजी सलीम कुरैशी सितंबर 2024 में शिवसेना के एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो गए थे। उनकी पत्नी गुलनाज सलीम कुरैशी बांद्रा (ईस्ट) के प्रभाग 92 की नगरसेविका रह चुकी हैं। हाजी के शिवसेना शिंदे में जाने से शिवसेना शिंदे को मजूबत बताया जा रहा है। खेरवाड़ी पुलिस हमलावर की पहचान करने के लिए इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही थी। मुंबई में बीएमसी चुनावों के लिए 15 जनवरी को वोट डाले जाएंगे जबकि मतों की गिनती 16 जनवरी को होगी।

शिंदे को टक्कर देने की BJP की रणनीति: ठाकरे शिवसेना में बड़े प्रवेश और अजित पवार पर आरोप

मुंबई : महाराष्ट्र की राजनीति में आगामी मुंबई नगर निगम चुनाव 2026 से पहले BJP द्वारा एकनाथ शिंदे-नेतृत्व वाली शिवसेना को टक्कर देने की रणनीति तेजी से उभर रही है। ठाणे जिले में BJP ने अंबरनाथ नगर परिषद में अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कांग्रेस के 12 नगरसेवकों को अपने पक्ष में खींचा, जिससे शिंदे गुट को स्थानिक राजनीति में झटका लगा है और उसे विरोधी दल की भूमिका में बैठना पड़ रहा है।

इसी बीच उद्धव ठाकरे नेतृत्व वाली शिवसेना (UBT) में भी बड़े नेताओं और समर्थकों का प्रवेश हुआ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक जाधव के पुत्र कुNAL जाधव समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शिवसेना UBT में शामिल होकर महापालिका चुनाव के प्रभार को और मजबूत किया है। इस प्रवेश समारोह में उद्धव ठाकरे और कई स्थानीय पदाधिकारी उपस्थित रहे, जो चुनावी मुकाबले की रणनीति को सुदृढ़ करने का संकेत माना जा रहा है।

राजनीतिक बयानबाज़ी भी तेज़ है। BJP के एक विधायक महेश लांडगे ने उपमुख्यमंत्री अजित पवार पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वालों में शामिल होने के बावजूद अब उन्हीं के साथ गठबंधन में शामिल होने का आरोप लगाया है। BJP का दावा है कि पवार द्वारा पहले लगाए गए भ्रष्टाचार आरोपों को पार्टी अपने सत्ता में बने रहने के लिए नजरअंदाज़ कर रही है।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस समय सभी दल बीएमसी चुनाव को लेकर संगठन मजबूत करने में लगे हैं। BJP शिंदे गुट को कमजोर करने के लिए स्थानीय स्तर पर गठबंधन और अभिसरण की रणनीति अपना रही है, जबकि शिवसेना UBT अपने में नए चेहरों को शामिल कर अपनी चुनावी ताकत बढ़ा रही है। इस रणनीतिक परिदृश्य के बीच चुनावी राजनीति और भी रोमांचक और प्रतिस्पर्धात्मक होती जा रही है।

महाराष्ट्र में तापमान में तेज गिरावट, विदर्भ-मराठवाडा और पुणे में सिंगल डिजिट रीडिंग्स दर्ज

पुणे: महाराष्ट्र के कई हिस्सों में ठंडी हवाओं के लौटने से तापमान में तेज गिरावट आई है और विदर्भ, मराठवाड़ा तथा पुणे क्षेत्रों में रात के तापमान सिंगल डिजिट तक पहुँच गए हैं। इस वर्ष की सर्दी की शुरुआत में कुछ राहत मिली थी, लेकिन अब फिर से न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी जा रही है, जिससे लोगों को ठंड का अहसास बढ़ गया है |

हवामान विभाग के अनुसार, उत्तरी शीत हवाओं, साफ़ आसमान और शुष्क मौसम के कारण तापमान कम हुआ है और कई स्थानों पर एक अंक में रीडिंग दर्ज हुई है पुणे सहित कई इलाकों में ठंड का असर बढ़ा है और आने वाले दिनों में यही ठंडा मौसम बना रहने का अनुमान है। स्थानीय लोगों को सुबह-सुबह सर्दी का अधिक सामना करना पड़ रहा है और मौसम विभाग ने नागरिकों से ठंड के दौरान सावधानियां बरतने की अपील की है।

PCMC चुनाव 2026: पिंपरी-चिंचवड़ में बीजेपी सरकार पर दडपशाही व भ्रष्टाचार के आरोप, अजित पवार ने कसा हमला

पिंपरी-चिंचवड़ : आगामी पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका चुनाव 2026 से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक कांग्रेस (NCP) के नेता और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर कड़े आरोप लगाए हैं। पवार ने कहा कि पिंपरी-चिंचवड़ में बीजेपी की सरकार के दौरान जबरदस्ती फैसले लिए जाते हैं और गलत कार्यों पर फाइलों पर सही न करने वालों को धमकाया जाता है, जिससे अधिकारी स्वयंसेवानिवृत्त होने को मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने स्थानीय लोगों के बीच दहशत का माहौल होने का भी दावा किया है।

पवार ने भोसरी में शीतलबाग पादचारी पुल परियोजना का उदाहरण देते हुए कहा कि इसे शुरू में सत्तर लाख रुपये के बजट में दिया गया था, लेकिन पूरा होने तक खर्च सात करोड़ रुपये पहुंच गया। उन्होंने सवाल उठाया कि इस प्रकार के कार्यों से शहर का क्या भला हुआ और जनता को इससे क्या फायदा मिला।

पवार ने न सिर्फ भ्रष्टाचार बल्कि महापालिका में धन के दुरुपयोग और सीसीटीवी कैमरों के बंद पड़े होने जैसे मुद्दों को भी बड़े पैमाने पर उठाया।

उन्होंने कहा कि महापालिका में भ्रष्ट प्रशासन, कचरा प्रबंधन की विफलता,अनियमित योजनाओं और अनुचित कार्यप्रणाली ने शहर की स्थिति खराब कर दी है। पवार ने जनता से अपील की कि वह भाजपा के शासन को बदलने के लिए सोचें और बदलाव की दिशा में कदम उठाएं।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बयानबाज़ी चुनावी युद्ध के बीच जारी तनाव को दर्शाती है, जहाँ पिंपरी-चिंचवड़ की प्रमुख सियासी ताकतें अपने चुनावी संदेशों को जनता तक पहुंचाने में जुटी हैं। भाजपा ने अभी तक इन आरोपों पर प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन कहा जा रहा है कि वह अपने शासन के रिकॉर्ड का बचाव करेगी और आगामी चुनाव में बेहतर सार्वजनिक सेवा प्रदान करने का दावा करेगी।

मुंबई में खाली लोकल ट्रेन में लगी आग, कुर्ला-विद्याविहार के बीच रेल सेवा ठप, कोई हताहत नहीं

मुंबई: आज रात कुर्ला और विद्याविहार के बीच स्टेशन के पास खड़ी एक खाली लोकल ट्रेन के डब्बे में अचानक आग लग गई, जिससे मध्य रेल्वे की 'स्लो' लाइन पर यातायात प्रभावित हुआ और ट्रेन सेवाएँ करीब आधे घंटे के लिए बाधित रहीं। यह घटना लगभग रात 8.30 बजे के आसपास हुई, जब कचरा व माल ढोने वाली एक विशेष लोकल ट्रेन के पहले डिब्बे में भड़क उठी आग ने स्थानीय रेलवे यार्ड में फैलकर परिस्थितियों को तनावपूर्ण बना दिया।

रेल अधिकारियों के अनुसार, आग इतनी तीव्र थी कि सुरक्षा कारणों से क्षेत्र में ओवरहेड केबल (OHE) की विद्युत आपूर्ति को लगभग 25 मिनट के लिए बंद करना पड़ा, जिससे सीएसएमटी की ओर जाने वाली स्लो लोकल सेवाएँ अस्थायी रूप से बंद हो गईं। हालांकि, दमकल कर्मियों और रेलवे स्टाफ की तत्काल प्रतिक्रिया से आग को नियंत्रण में ला लिया गया और कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ।

आग की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन स्थानीय रेल प्रशासन इस घटना की जांच कर रहा है। आग बुझाए जाने के बाद ट्रेन सेवा धीरे-धीरे पुनः शुरू कर दी गई, लेकिन कुछ मार्गों पर चल रही सेवाओं में देरी देखने को मिली। घटना के दौरान हुई रुकावट के बावजूद रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से संयम बनाए रखने और आगामी सेवा अपडेट के लिए सूचनाओं पर ध्यान देने का आग्रह किया है।

मुंबईकरों के लिए लोकल ट्रेन जीवन-रेखा है, ऐसे में इस तरह की अप्रत्याशित घटनाएँ उनकी यात्रा योजनाओं पर असर डाल सकती हैं। रेलवे प्रशासन ने safety मानकों को और अधिक कड़ाई से लागू करने का वादा किया है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं से समय पर निपटा जा सके।

नांदेड़ वॉक्स

नांदेड़ जिला > नांदेड़ शहर

नंदिग्राम टाईम्स

Friday 9th January 2026 वर्ष - 9 , अंक 254 , पृष्ठ 04

नांदेड चुनाव प्रचार: परिवार काम छोड़कर जुटे रैलियों में, एजेंट भीड़ जुटाने में जुटे

नांदेड : नांदेड-वाघाळा महानगरपालिका 2026 द्वाराच्या निकट, चुनाव प्रचार का रंग तेजी से बढ़ा है। कई लोग अपने रोज़गार को अलविदा कहकर पूरी परिवार समेत राजनीतिक रैलियों और सभाओं में भाग ले रहे हैं, क्योंकि प्रचार के दौरान भुगतान किए जा रहे हैं, जिससे वे हाथ में अधिक कमा पा रहे हैं | भाड़ोत्री एजेंट सक्रिय हैं और प्रत्येक रैली या सभा के लिए कार्यकर्ताओं को लाने के लिए 500 रुपये तक दिए जा रहे हैं। इन एजेंटों को उम्मीदवारों की ओर से कार्यक्रमों में भीड़ जुटाने हेतु 5,000 से 10,000 रुपये तक मिलते हैं |

कई लोग, जिन्हें प्रचार के उम्मीदवार या पार्टी का नाम भी सही-से मालूम नहीं है, वे भी पारिवारिक सदस्य के साथ झंडा लेकर रैलियों में भाग ले रहे हैं। कार्यकर्ता सुबह के काम को छोड़कर, कुछ घंटों के लिए झंडा और बैनर के साथ रैलियों में शामिल होकर आसानी से पैसे कमा रहे हैं| इस तरह चुनाव प्रचार अब न केवल राजनीतिक गतिविधि बन गया है, बल्कि कुछ लोगों के लिए अस्थायी आय का साधन भी बन गया है, जिससे स्थानीय राजनीति और प्रचार के स्वरूप में बदलाव दिखाई दे रहा है।

मतदान में सिर्फ सात दिन शेष, नांदेड मनपा की अंतिम लड़ाई अब भी धुंधली

नांदेड। नांदेड-वाघाळा शहर महानगरपालिका चुनाव के मतदान में अब केवल सात दिन शेष रह गए हैं। आगामी गुरुवार को होने वाले मतदान से पहले राजनीतिक सरगर्मी जरूर बढ़ी है, लेकिन अब तक अंतिम मुकाबले की तस्वीर पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाई है। किस दल के सिर ताज सजेगा, यह आने वाले कुछ दिनों में ही तय हो सकेगा।

नांदेड-वाघाळा शहर महानगरपालिका के कुल 20 प्रभागों से 81 नगरसेवकों का चुनाव होना है। इस चुनावी मैदान में भाजपा, शिवसेना (शिंदे गुट), शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे), कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस (अजीत पवार), राष्ट्रवादी कांग्रेस (शरद पवार), वंचित बहुजन आघाड़ी, एमआईएम सहित प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ कुल 491 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।

4 जनवरी से प्रत्यक्ष प्रचार शुरू हो चुका है, लेकिन अब तक प्रचार में वह तीव्रता नजर नहीं आ रही, जिसकी अपेक्षा की जा रही थी।

इस बीच भाजपा ने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सभा आयोजित कर चुनावी माहौल बनाने की कोशिश की। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री व सांसद अशोकराव चव्हाण की सभाओं का सिलसिला भी शुरू हो गया है। मुस्लिम बहुल इलाकों में एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने प्रचार सभाएं कर अपने उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल बनाया। वहीं वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय नेता एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर और उनके पुत्र सुजात आंबेडकर ने भी चुनावी सभाओं के जरिए ताकत झोंकी है।

कांग्रेस उम्मीदवारों के प्रचार की जिम्मेदारी सांसद रविंद्र चव्हाण ने संभाली है। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) की ओर से तरोडा क्षेत्र में सांसद नागेश पाटील आष्टीकर ने पदयात्रा निकालकर जनसंपर्क किया। नांदेड उत्तर विधानसभा क्षेत्र में शिवसेना उम्मीदवारों के प्रचार की कमान विधायक बालाजीराव कल्याणकर ने संभाली है,जबकि नांदेड दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में शिवसेना के उपनेता विधायक हेमंत पाटील और विधायक आनंदराव बोंढारकर प्रचार सभाएं ले रहे हैं। गौरतलब है कि नांदेड दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस (अजीत पवार) के बीच गठबंधन हुआ है और दोनों दल समन्वय के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं शिवसेना और भाजपा के बीच गठबंधन न होने के कारण दोनों दल आमने-सामने हैं।

मतदान में अब महज एक सप्ताह का समय बचा है, लेकिन शहर के विभिन्न प्रभागों में अभी भी मुकाबला रोचक और अनिश्चित बना हुआ है। आने वाले दिनों में किन-किन बड़े नेताओं की सभाएं होती हैं और उनका मतदाताओं पर कितना असर पड़ता है, उसी से नांदेड मनपा चुनाव की अंतिम तस्वीर साफ होने की उम्मीद जताई जा रही है।

नांदेड के विकास के लिए भाजपा का महापौर बनाएं : सांसद अशोकराव चव्हाण

नांदेड : शहर का सर्वांगीण विकास तभी संभव है, जब नांदेड-वाघाला महानगरपालिका में भाजपा की सत्ता होगी। इसके लिए मतदाताओं को भाजपा के उम्मीदवारों को भारी मतों से विजयी बनाना चाहिए। यह अपील सांसद अशोकराव चव्हाण ने शहर में आयोजित कॉर्नर सभाओं के दौरान की।

बुधवार को वार्ड क्रमांक 5, 15 और 16 में आयोजित बैठकों को संबोधित करते हुए सांसद चव्हाण ने कहा कि वर्षों से लंबित खिदमत और मदतमाश जमीनों का मुद्दा भाजपा सरकार के प्रयासों से सुलझने की दिशा में है। पूर्व राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील द्वारा इस विषय को आगे बढ़ाया गया, जबकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और वर्तमान राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे के नेतृत्व में इसे स्थायी समाधान मिला।

उन्होंने बताया कि लंबे समय से शासकीय जमीनों पर रह रहे पात्र नागरिकों को उसी स्थान पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घरकुल का लाभ दिलाया जाएगा। सांसद चव्हाण ने कहा कि भाजपा झूठे वादों के बजाय सच्चाई के साथ जनता से समर्थन मांगती है।

विरोधियों पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग हर विकास कार्य का श्रेय लेने का दावा कर रहे हैं, संभव है वे ताजमहल और गेटवे ऑफ इंडिया के निर्माण का भी दावा करें। ऐसे दावों से प्रभावित हुए बिना मतदाताओं को शहर और वार्ड के विकास के लिए भाजपा के अधिकाधिक नगरसेवक और महापौर चुनने चाहिए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाजपा में प्रवेश किया।

हिमायतनगर नगरपंचायत में नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष शेख रफीकभाई का पदग्रहण संपन्न

हिमायतनगर नगरपंचायत कार्यालय में नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष एवं नगरसेवकों का पदग्रहण समारोह उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित रहे पूर्व विधायक माधवराव पाटील जवलगांवकर का नगराध्यक्ष शेख रफीकभाई एवं अन्य नगरसेवकों द्वारा पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मान किया गया।

समारोह के दौरान पूर्व विधायक माधवराव पाटील जवलगांवकर ने नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए कहा कि नगर के सर्वांगीण विकास के लिए सभी जनप्रतिनिधियों को मिल-जुलकर कार्य करना चाहिए। उन्होंने जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए पारदर्शी और संवेदनशील प्रशासन देने का आह्वान किया।

नगराध्यक्ष शेख रफीकभाई ने अपने संबोधन में कहा कि हिमायतनगर के विकास को नई गति देने के लिए नगरपंचायत सदैव प्रतिबद्ध रहेगी। बुनियादी सुविधाओं, स्वच्छता, जलापूर्ति और नागरिक सेवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने पूर्व विधायक के मार्गदर्शन को नगर के लिए प्रेरणादायी बताया।

कार्यक्रम में नगरसेवक, नगरपंचायत के अधिकारी-कर्मचारी, गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित थे। समारोह सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ।

नांदेड में जिला प्रशासन की अनोखी पहल 'ई-डाकिया सेवा', व्हॉट्सऐप पर मिलेगी आवेदनों की त्वरित जानकारी

नांदेड, 8 जनवरी। (जिमाका,नांदेड़) : राज्य के माननीय मुख्यमंत्री की संकल्पना से लागू किए जा रहे 150 दिवसीय ई-गवर्नेंस सुधार कार्यक्रम के तहत नांदेड जिला प्रशासन ने नागरिकों की सुविधा के लिए एक अभिनव और जनहितकारी पहल 'ई-डाकिया सेवा' शुरू की है। इस सेवा के माध्यम से अब जिलाधिकारी कार्यालय में दिए गए आवेदनों पर की गई कार्यवाही की जानकारी सीधे नागरिकों के व्हॉट्सऐप पर भेजी जाएगी। यह जानकारी जिलाधिकारी राहुल कर्डिले ने दी।

इस सेवा के शुरू होने से नागरिकों को अपने आवेदन की स्थिति जानने के लिए बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जिलाधिकारी कार्यालय में आवेदन या पत्र जमा करते समय नागरिकों को उसमें अपना व्हॉट्सऐप नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद संबंधित आवेदन पर हुई कार्रवाई की जानकारी घर बैठे उनके मोबाइल पर उपलब्ध करा दी जाएगी।

महाराष्ट्र में पहली बार नांदेड जिलाधिकारी कार्यालय में यह अनोखा उपक्रम शुरू किया गया है। केवल पिछले दो दिनों में ही लगभग 1,500 नागरिकों को 'ई-डाकिया सेवा' के माध्यम से जानकारी प्रदान की जा चुकी है। इसके साथ ही आगामी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग की गट-क परीक्षा के लिए नियुक्त किए गए 577 अधिकारी-कर्मचारियों को भी उनके नियुक्ति आदेश सीधे व्हॉट्सऐप के जरिए भेजे गए हैं।

जिला प्रशासन का मानना है कि यह पहल प्रशासन को अधिक लोकाभिमुख, पारदर्शी, त्वरित और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रशासन ने अधिक से अधिक नागरिकों से इस सेवा का लाभ उठाने का आग्रह किया है।

इस अभिनव सेवा को सफलतापूर्वक लागू करने में आईटी कंसल्टेंट संतोष निलावर और मुख्यमंत्री फेलो आर्थव मोडक ने विशेष योगदान दिया है।

अवैध रेत खनन पर जिलाधिकारी की सख्त कार्रवाई, वाहन व मशीनें जब्त; 18.38 लाख रुपये का जुर्माना

संवाददाता |

नांदेड, (जिमाका,नांदेड) : जिले में अवैध रेत खनन और परिवहन के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी राहुल कर्डिले के निर्देश पर लोहा तालुका अंतर्गत कौडगांव में बुधवार सायंकाल अचानक छापेमारी कर अवैध रेत के कारोबार पर करारा प्रहार किया गया।

इस कार्रवाई में रेत से भरा एक हाइवा ट्रक, दो जेसीबी पोकलेन मशीनें तथा लगभग 40 ब्रास अवैध रेत का भंडार जब्त किया गया है। अवैध रूप से रेत परिवहन कर रहे हाइवा ट्रक पर राजस्व विभाग द्वारा 2 लाख 83 हजार रुपये तथा परिवहन विभाग द्वारा 55 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

इसके अलावा, अवैध उत्खनन में प्रयुक्त दो जेसीबी पोकलेन मशीनों पर परिवहन विभाग की ओर से प्रति मशीन 7 लाख 50 हजार रुपये का दंड लगाया गया है। इस प्रकार कुल मिलाकर 18 लाख 38 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया है, ऐसी जानकारी जिला प्रशासन ने दी।

इस संयुक्त कार्रवाई में लोहा के तहसीलदार विठ्ठल परळीकर, नायब तहसीलदार श्री पाठक, उस्माननगर पुलिस स्टेशन के सहायक पुलिस निरीक्षक निलपत्तेवार सहित राजस्व व पुलिस विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध रेत खनन व परिवहन के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार की कठोर कार्रवाई जारी रहेगी तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

नांदेड में NCP के MLA प्रताप पाटिल चिखलिकर का निशाना: BJP 'प्रायवेट लिमिटेड', अशोक चव्हाण पर तीखी बात

नांदेड, 8 जनवरी 2026: नांदेड में महापालिका चुनाव प्रचार के दौरान राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (NCP) के विधायक प्रताप पाटिल चिखलिकर ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता अशोक चव्हाण पर कड़े आरोप लगाए। उन्होंने भाजपा को "प्रायवेट लिमिटेड" बताया और कहा कि नांदेड में भाजपा का गठन पार्टी से अधिक किसी निजी कंपनी जैसा दिखाई दे रहा है।

चिखलिकर ने अपने संबोधन में बताया कि भाजपा ने न सिर्फ अपने मूल राजनीतिक सिद्धांतों को पीछे छोड़ा है, बल्कि स्थानीय जनता की उम्मीदों और मूल्यों के साथ भी खिलवाड़ किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि इसी तरह का राजनीतिक व्यवहार जारी रहा तो नांदेड की जनता भाजपा को नहीं बल्कि NCP को चुनाव में विजयी बनाएगी। उनका यह बयान महापालिका चुनाव के मद्देनजर तेज़ राजनीतिक हलचल के बीच आया है।

वीडियो में चिखलिकर यह भी कहते सुने गए कि "चोर को चोर कहना अगर किसी को बुरा लगता है तो मजबूरी है।" इससे स्पष्ट होता है कि उन्होंने भाजपा के शासन और स्थानीय मुद्दों के समाधान में उसके रवैये पर कठोर टिप्पणी की।

चिखलिकर की इस टिप्पणी को महायुति गठबंधन के भीतर जारी तनाव का संकेत भी माना जा रहा है, जहां सहयोगी दल एक-दूसरे पर आरोप लगाने से नहीं हिचक रहे हैं। यह बयान स्थानीय राजनीति में जारी प्रतिस्पर्धा और गठबंधन की कमजोर कड़ियों को उजागर करता है, खासकर तब जब दोनों प्रमुख राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियाँ आगामी चुनावों के लिए तैयारी कर रही हैं।

इस दौरान भाजपा के नेताओं की ओर से चिखलिकर के आरोपों पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, नांदेड में यह बयान आगामी चुनावी रणनीतियों को प्रभावित कर सकता है और स्थानीय जनसमर्थन को दो समूहों में बांट सकता है।

बालविवाह रोकने जिल्हाधिकारी ने जारी किए कड़े निर्देश, मंगल कार्यालय और धार्मिक स्थलों में वय प्रमाण अनिवार्य

नांदेड, ८ जनवरी (जिमाका,नांदेड़) : नांदेड जिल्हा प्रशासन ने बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम, २००६ के तहत जिले में बालविवाह की घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। जिल्हाधिकारी और बालविवाह निर्मूलन जिल्हा कार्यदल के अध्यक्ष राहुल कर्डिले ने सभी मंगल कार्यालयों और धार्मिक स्थलों को निर्देशित किया है कि विवाह आयोजन से पहले वधू और वर की उम्र की प्रमाणिक जांच अनिवार्य रूप से की जाए।

निर्देशों के अनुसार, विवाह में वधू की न्यूनतम उम्र १८ वर्ष और वर की न्यूनतम उम्र २१ वर्ष होनी चाहिए। इसके लिए आधार कार्ड मान्य दस्तावेज नहीं माना जाएगा। केवल जन्म प्रमाण पत्र, शालेय कागजात जैसे बोनाफाइड प्रमाणपत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र या प्रवेश-निकास प्रमाण पत्र के आधार पर ही उम्र की पुष्टि की जाएगी। प्रशासन ने यह कदम इसलिए उठाया है, क्योंकि कई मामलों में आधार कार्ड और शैक्षणिक दस्तावेजों में जन्मतिथि में अंतर पाया गया है, जिससे बालविवाह की घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। जिल्हाधिकारी ने स्पष्ट किया कि यदि कानूनी विवाह योग्य आयु पूरी न होने पर कोई विवाह आयोजित किया गया, तो विवाह स्थल को अनुमति देने वाले या बालविवाह को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी मंगल कार्यालयों और धार्मिक स्थलों में इस संबंध में सूचना फलक भी लगाए जाने निर्देशित किए गए हैं।

प्रशासन ने नागरिकों से भी अपील की है कि अगर कहीं बालविवाह की सूचना मिलती है तो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामसेवक, शहरी क्षेत्रों में बाल विकास परियोजना अधिकारी, जिल्हा महिला और बाल विकास अधिकारी कार्यालय नांदेड या चाइल्ड हेल्पलाइन १०९८ पर तुरंत संपर्क करें।

जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले ने कहा कि बालविवाहमुक्त नांदेड जिले के निर्माण में नागरिकों, मंगल कार्यालयों और धार्मिक संस्थाओं का सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने का भी आह्वान किया।

स्वाधिकारी नंदिग्राम टाईम्स (नांदेड़) के मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक शेख जहूर शेख अहेमद द्वारा सहारा डिजाइनिंग एंड ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस, वाजेगांव, ता. व जि. नांदेड़ में मुद्रित तथा दैनिक नंदिग्राम टाईम्स, मुल्लाह मार्केट, खवी बिल्डिंग, नगरेश्वर मंदिर, नांदेड़–431604 (महाराष्ट्र) के कार्यालय से प्रकाशित। RNI-MAHHIN/2016/69743 मोबाइल संपर्क: 9921100075 | Email: ntinfodesk@gmail.com (वाद-विवाद हेतु न्यायक्षेत्र: नांदेड़ न्याय कक्षा में।)